Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 22-05-2006

Participants : Suman Shri Ramji Lal

an>

Title : Need to take steps for educational development of SCs/STs with a view to enable them to take the benefit of reservations in Government jobs.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, आरक्षण नीति का क्रियान्वयन एक मंजिल की राह है, स्वयं मंजिल नहीं। देश को स्वतंत्र हुए अर्धशताब्दि बीत चुकी है इसी के साथ आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की अवधि भी इतनी ही हो चुकी है। दरअसल मंजिल है समाज के दलित व पिछडे वर्ग का उत्थान और इसी के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन होता आ रहा है, धरातल की वास्तविकता यह है कि आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों के कोटे के स्थान रिक्त पड़े हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार ही ए.बी.सी.डी श्रेणी की सभी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.52 है एवं अनुसूचित जनजाति का तो मात्र 6.46 प्रतिशत और इसके लिए यदि यह कहा जाए कि योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धि न होना ही स्थानों के रिक्त होने का प्रमुख कारण है तो यह दायित्व भी सरकार का है कि वह समाज के दलित व दयनीय वर्ग को प्रोत्साहित करके सबल और योग्य नहीं बना पा रही है।

अतः मेरा आग्रह है कि सरकार आरक्षण नीति को शब्दशः क्रियान्वित करने की मौजूदा परिपाटी के साथ समाज में दलित व पिछड़े वर्ग के वास्तविक उत्थान और विकास के मंजिल व उद्देश्य को पाने के लिए संबंधित सभी अन्य क्षेत्रों में कारगर कदम उठाये।